coke that they are receiving is high-priced as compared to what is paid by the small-scale industries in the north and they have claimed that they should also get them at the same price. I would like to know whether the Minister, whose heart he claims is in developing small-scale industries, will raise the problem with his colleague, the unenergetic Minister of Energy and see that they are supplied to them at a cheaper price. Secondly, because this is raw material....

MR. SPEAKER: This is not raw material; this is a question.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Coal and coke are the raw materials required for the industry. Secondly, I would also like to know from the hon. Minister what help is being given to the small-scale industries to develop the export market, particularly in the South East Asian and Arab countries, from where they are being squeezed out by bigger countries.

SHRI GEORGE FERNANDES: There are a number of export corporations which are taking care of the export problems. There has not been any specific complaint made to me about the small-scale industries having any problem about exporting what is manufactured by them. In so far as the price of coal and coke is concerned, that is a question which will have to be examined by the Energy Ministry, and the hon. Member is free to make a reference to the Energy Ministry.

नये सीमेंट कारखानों की स्थापना

*154. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या सरकार सीमेंट की मांग पूरी करने के विचार से छठी योजना में नये सीमेंट कारखाने लगाने की अनुमति देगी ;

(ग) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां लगाये जायेंगे और उन की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) इन कारखानों में उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1977–78 में 192.8 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो अब तक का सर्वाधिक किया गया उत्पादन है । रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी कृषि, गृह-निर्माण, सिंचाई और विद्युत आदि क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सीमेंट की बढ़ी हुई मांग के कारण देश के विभिन्न भागों में सीमेंट की कमी हुई है ।

सीमेंट उद्योग की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 218.70 लाख मी० टन है । इसके अलावा आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंसों के माध्यम से 194.80 लाख मी० टन की और अधिक क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है 118 लाख मी० टन की और अधिक क्षमता बढ़ाने से संबंधित आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न स्थितियों में हैं । विद्यमान क्षमता स्वीकृत किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों तथा विचाराधीन न पड़े हुए आवेदन पत्रों की ब्यौरेवार जानकारी देने वाले पांच विवरण सभा पटल पर रख दिए गये हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या Lt—2488/78] । सीमेंट स्थापित करने के लिए जैसे ही और आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उन पर गुणा-व-गुणों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । सीमेंट उद्योग के पनपने की अवधि आम तौर से 4–5 वर्ष की होती है । सरकार

विद्यमान क्षमता के 100 प्रतिशत उपयोग और निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सीमेंट की वर्तमान उत्पादन क्षमता 19.28 मिलियन टन है और शासन की ओर से दिए गए लाइसेंसेज के आधार पर उत्पादन 19.48 मिलियन टन बढ़ जायगा । माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वयं भी स्वीकार किया है कि यह उत्पादन अगले चार-पांच वर्षों में जाकर पूरा होगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समय जो कमी है और जो सरकार के सामने अभाव का क्राइसिस है इस को दूर करने के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ?

SHRI GEORGE FERNANDES: There are a number of on-going cement projects and some of them will be completed in the course of this year, and some next year. These will enable us to meet some of the present shortages. Besides, we have taken steps to see that during the next eight months in any case our cement units produce one hundred per cent of their capacity. We are doing everything necessary to monitor their production, and we are hopeful of achieving this target. Thirdly, so far as the present shortage is concerned, we are also importing cement. A considerable amount of cement has been imported and is being imported, and we will see that the shortages are met.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा । माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट की वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्दर अनेक त्रुटियां होने के कारण बड़े गम्भीर परिणाम हो रहे हैं तथा जनता में असंतोष व्याप्त है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है । अतः सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट दिलवाने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

इसके साथ ही साथ जहां तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में जो सीमेन्ट का उत्पादन हो रहा है उस सीमेन्ट को राजस्थान भेजा जा रहा है और राजस्थान में जो सीमेंट का उत्पादन हो रहा है उस को उत्तर प्रदेश में भिजवाया जा रहा है तो इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं । इस के साथ ही उत्तर प्रदेश इस देश का सब से बड़ा प्रदेश होते हुए भी वहां पर अन्य प्रदेशों के अनुपात में सब से कम सीमेन्ट दिया जा रहा है । इस कमी को दूर करने के लिए तथा वितरण प्रणाली को दूर ठीक करने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक वितरण प्रणाली की बात है, दो सवाल हैं—एक तो यह कि सीमेन्ट किस तरह से कहां भेजी जाये, इस में जो अब तक स्थिति रही है उसको सुधारने के काम में हम लगे हैं और जितना भी सम्भव है वह काम हम करेंगे । जहां तक इस बात का सवाल है कि किस माध्यम से सीमेंट का वितरण हो, इसके बारे में हमने हर राज्य सरकार से कहा है कि अगर सरकार कोआपरेटिव सोसायटी या किसी और संस्था के माध्यम से इसका वितरण करना चाहे तो हम उनको हर प्रकार की मदद देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अक्तूबर से खुद ही वितरण करने का निर्णय लिया है, गुजरात सरकार ने भी इसी तरह की इत्तला दी है और दिल्ली प्रशासन भी इसी तरह की बात सोच रहा है । अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहे तो हम उनको हर प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं ।

———